Amendment to National Highways Act

804. SHRI GHUFRAN AZAM: Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether Government propose tO' amend tiie National Highways Act;

(b) if so, the reasons; herefor;

(c) whether it is a fact that the condition of National Highways throughout the country is in a very bad shape;

(dj if so, how much expenditure has been incurred by the Central Government to repair the National Highways during the past three years, year-wise; and

(e) what further steps Government propose to contemplate to maintain National Highways?

THE MINISTER OF WATER RE SOURCES WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTRY OF SUR FACE TRANSPORT (SHRI MANUBHAI 'KOTADIA): (a) and (b) Yes, Sir. In order to mobilise additional resources.

(c) and (d) National Highways in the country are generally in a traffic worthy condition and improvement works are undertaken keeping in view the existing condition, traffic intensity, inter-se prioity on an All-India basis and availability of funds. Expenditure incurred on maintenance of various National Highways during the past three years is as under: - —

1987-88	Rs. 10, 915. 76 lacs
1988-89	Rs. 14, 634. 61 lacs
1989-90	Rs. 15, 796. 29 lacs

(e) Introduction of computer-aided pavement Management System for optimal utilisation of available scarce resources.

नेपाल में पाकिस्तान समर्थक आतंकवादियों द्वारा अड्डे बनाये जाना

805. **श्री राम जेठमलानी :**
श्री हलराम सिंह यादव :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इन समाचारों की ओर दिलाया गया है कि कश्मीर के अनेक पकिस्तान समर्थक आतंकवादी संगठन अपनी गतिविधियां चलाने के लिए नेपाल में अपने अड्डे बना रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में नेपाल सरकार के साथ बात की है ;

(ग) क्या नेपाल में इन अड्डों से निपटने के लिए संयुक्त कार्रवाई करने के संबंध में दोनों देशों में कोई समझौता है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी हां ।

(ख) से (घ) नेपाल और भारत की सरकारों के बीच समुचित स्तरों पर इसके संबंध में विचार-विमर्श होता रहा है । 25–26 नवम्बर, 1990 की हाल की अपनी नई दिल्ली की यात्रा के दौरान नेपाल के प्रधानमंत्री श्री कृष्ण प्रसाद भट्टाराई ने कहा था कि अगर नेपाल राज्य में किसी कश्मीरी अथवा पंजाबी आतंकवादी को शरण देने का कोई मामला उनकी जानकारी में आता है तो वे सख्त कार्रवाई करेंगे । तथापि इस प्रकार के मामलों से संबद्ध कोई औपचारिक द्विपक्षीय समझौता नहीं है ।

फिजी में भारतीय मूल के लोगों के साथ भेदभाव

806. **श्री राम जेठमलानी :**
डा० जितेन्द्र कुमार जैन :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 30 जुलाई, 1990 के "द हिन्दू" से "रिटर्न टू द मदरलैंड" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ; यदि हां तो क्या यह सच है कि फिजी में भारतीय मूल के लोगों के साथ भेद भावपूर्ण और अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है ; और

(ख) क्या यह भी सच है कि इस व्यवहार के कारण फिजी के नागरिकों को फिजी छोड कर किसी अन्य देश में जाने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है ; यदि हां, तो चालू वर्ष में फिजी छोड़ कर जाने वाले लोगों की संख्या क्या है और क्या सरकार ने इस संबंध में कूटनीतिक कदम उठाए हैं, यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है और उनका क्या परिणाम निकला है ?

विदेश मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख) फिजी में भारतीय मूल के लोगों के साथ जो जातीय भेदभाव का व्यावहार किया जा रहा है उसके प्रति तथा वहां की गैर-कानूनी सरकार द्वारा फिजी के नागरिकों के मानवाधिकारों का जो उल्लंघन हो रहा है उसकी भी भारत सरकार की जानकारी है । इसकी वजह से पिछले तीन साल में करीब 21,000 लोग वहाँ से विदेशों में चले गए हैं; लेकिन बताया जाता है कि कुछ लोग लौट भी आए हैं । वर्ष 1990-91 के ठीक-ठीक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं । भारत सरकार ने कई अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर फिजी में जातीय भेदभाव तथा मानवाधिकारों के उल्लंघन का सवाल उठाया है। सम्बद्ध देशों के साथ द्विपक्षीय बैठकों में भी इस संबंध में विचार-विमर्श हुआ है । भारत सरकार जातीय भेद-भाव का तथा फिजी में मानवाधिकारों के उल्लंघन का विरोध करने वाले सभी फिजी वासियों को राजनयिक और नैतिक समर्थन दे रही है । फिजी की स्थिति के प्रति अन्तर-राष्ट्रीय जागरुकता यद्यपि बढ़ रही है लेकिन अन्य कुछ ही ऐसी सरकारें हैं जिन्होंने गैर-कानूनी सरकार की जातीय भेद-भाव की नीति का सक्रिय विरोध किया है ।

गंगा कार्य योजना

807. **श्री जलराम सिंह यादव :**
डा० जितेन्द्र कुमार जैन :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश में गंगा कार्य योजना के अधीन शुरू की गई परियोजनाओं पर काम लगभग रोक दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उत्तर प्रदेश में इस योजना पर कितना धन व्यय किया है ;

(ग) व्यय किए गए धन से इस योजना के अंतर्गत कितना काम किया गया है ; और

(घ) इस कार्य योजना को अधूरा छोडने के क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) जी, नहीं । उत्तर प्रदेश में परियोजना की स्कीमों पर कार्य रुका नहीं है । संस्वीकृत की गई 107 स्कीमों में से 66 स्कीमें पहले ही पूरी की जा चुकी हैं । शेष स्कीमें कार्य पूरा होने के विभिन्न चरणों में है ।

(ख) दिनांक 31.10-90 तक 77.6 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च की जा चुकी है ।

(ग) हरिद्वार-ऋषिकेश में 16 स्कीमों, फतेहगढ़ फर्रुखाबाद में 3 स्कीमों; कानपुर में 7 स्कीमों, इलाहाबाद में 13 स्कीमें, मिर्जापुर में 2 स्कीमें और वाराणसी में 25 स्कीमों पर क्रमश: 11.05 करोड़ रुपये, 1.02 करोड़ रुपये, 12.45 करोड़ रुपये, 3 93 करोड़ रुपए, 2.90 करोड़ रुपये और 35.91 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं । शेष कार्य प्रगति पर है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

Financial assistance to Paradeep Port Trust

808. SHRI KAHNU CHARAN LENKA: Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether any proposal has been received from Ae Paradeep Port Trust for providing adequate financial assistance for the improvement of the existing iron-ore berths and ore handling plant at that port; and